भारत – जॉर्डन संबंध

भारत और जॉर्डन के बीच हमेशा सौहार्द एवं सद्भावनापूर्ण संबंध रहे हैं जो परस्पर विश्वास एवं सम्मान पर टिका हुआ है। इन दोनों देशों ने वर्ष 1947 में सहयोग तथा मित्रवत संबंधों के लिए अपने पहले द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए, जिसे इन दोनों देशों के पूर्णरूपेण राजनयिक संबंधों के स्थापित हो जाने के बाद वर्ष 1950 में औपचारिक रूप प्रदान किया गया। पिछले साल जन दर जन संपर्कों में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ मनाई गईं थी। नवंबर 2014 में भारत सरकार ने जार्डन के नागरिकों को ई - टीवी सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया। क्षमता निर्माण के प्रयासों में जार्डन की मदद करने के लिए आई सी सी आर के तहत अन्य छात्रवृत्तियों के अलावा 30 आई टी ई सी स्लाट उपलब्ध कराए गए हैं। भारत सरकार ने 2016-17 से आई टी ई सी स्लाटों की संख्या पुन: बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया है जैसा कि अक्टूबर 2015 में राष्ट्रपति जी की जार्डन की राजकीय यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। 29 और 30 मार्च को अमान में भारत - जार्डन संयुक्त व्यापार एवं आर्थिक समीति की बैठक के 9वें सत्र के दौरान अन्य बातों के साथ 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन अमरीकी डालर तक ले जाने और एक वार्षिक भारत - जार्डन व्यवसाय फोरम का आयोजन करने पर सहमति हुई।

बहुपक्षीय मंचों पर, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत, जॉर्डन के साथ हमारे परस्पर कार्रवाई की वजह से आपसी सरोकारों एवं प्राथमिकताओं के बारे में हमारी बेहतर समझ विकसित हुई है। जॉर्डन ने 2011-12 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए समर्थन किया था और भारत ने भी 2014-16 की अवधि के लिए इस सीट हेतु जॉर्डन की उम्मीदवारी हेतु अपनी ओर से महत्वपूर्ण सहायता की है। अक्टूबर 2014 में, न्यूयार्क में हमारे मिशन ने जॉर्डन के लिए आपात अनुक्रिया निधि हेतु न्यूर्याक में संयुक्त राष्ट्र को 5,00,000 अमेरीकी डॉलर का चेक प्रदान किया। शाह अब्दुल्ला ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करने का फिर से आश्वासन दिया। दोनों पक्ष डब्ल्यू टी ओ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी सहयोग करेंगे।

माननीय राष्ट्रपति जी ने 10 से 12 अक्टूबर 2015 के दौरान जार्डन की राजकीय यात्रा की जो भारत की ओर से एच ओ एस स्तर पर अब तक की पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जी ने महामहिम शाह अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला एनसोर और उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री नसीर एस जुडेह के साथ बैठक की। सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में छ: करारों / एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 2015-17, समुद्री परिवहन, भारतीय मानक ब्यूरो तथा जार्डन मानक एवं मौसम विज्ञान संगठन, भारत के विदेश सेवा संस्थान और जार्डन राजनय संस्थान के बीच करार शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों तथा जार्डन के उनके समकक्षों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए 10 एम ओ यू पर भी हस्ताक्षर किए गए। जार्डन विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति जी को डाक्टोरेट की मानद उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति जी ने सिनेटर प्रेसीडेंट तथा विदेश संबंध समिति के साथ अलग से भी बैठक की। उन्होंने महात्मा गांधी रोड का उद्घाटन भी किया तथा ओलिव का पौधा लगाया तथा उसे विश्व शांति के लिए समर्पित किया। दोनों नेताओं ने 860 मिलियन अमरीकी डालर के जिफको संयुक्त उद्यम का दूर से उद्घाटन किया। इससे पहले सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अतिरिक्त समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महामहिम शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की थी।

19 जून 2016 को अम्मान में विदेश मंत्री की ट्रांजिट यात्रा के दौरान महासचिव श्री मोहम्मद तसीर यासीन ने उनसे मुलाकात की।

दिसंबर, 2006 में जॉर्डन के महाराजा अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन तथा महारानी रानिया के भारत में महत्वपूर्ण सरकारी दौरे से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचारों के आदान–प्रदान का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हुआ। इस यात्रा के दौरान, अनेक द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए। जॉर्डन के शाही घराने के राजकुमार एल हसन बिन तलाल ने अक्टूबर – नवंबर, 2012 के दौरान भारत का दौरा किया।

श्री एस. एम. कृष्णा, तत्कालीन विदेश मंत्री ने सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ 8 एवं 11 जनवरी, 2012 को अम्मान का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारतीय पक्ष और महामहिम श्री नसीर एस जुडेह के नेतृत्व में जार्डन पक्ष ने आपसी हित के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की।

तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने रामाल्लाह (फिलीस्तीन) के दौरे के बीच में 20 नवंबर, 2011 को अम्मान में भी रूके। इस अल्पकालीन दौरे के दौरान, इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री एच. ई. श्री ऑन शौकत अल – खसावनेह से मुलाकात की। उन्होंनें ने 2–3 जुलाई, 2013 के दौरान जॉर्डन का पुन: सरकारी दौरा किया और 6 जुलाई, 2013 को जॉर्डन से होकर गुजरे। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री एनसौर एवं विदेश मंत्री नास्सेर जुदेह से मुलाकात की। इनकी बातचीत द्विपक्षीय संबंधों विशेषकर आर्थिक एवं वाणिजयिक क्षेत्रों तथा अद्यतन क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास के क्षेत्रों से संबद्ध मुद्दों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में हुई।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने फरवरी, 2010 को जॉर्डन का सरकारी दौरा किया। श्री ए. के. जैन, महासचिव, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने 3-6 अगस्त, 2009 को अम्मान में एशिया प्रशांत मानव अधिकार मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।

डा. चरणजीत सिंह अटवाल, माननीय अध्यक्ष पंजाब विधान सभा और उनकी पत्नी तथा सचिव, पंजाब विधान सभा ने 22–25 सितंबर, 2012 के दौरान अम्मान के सरकारी दौरे पर रहे। माननीय अध्यक्ष ने श्री अटेफ अल. तारावनेह, डिप्टी स्पीकर, हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ऑफ द हाशेमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन के साथ मुलाकात की। उनकी संसदीय सहयोग के मुद्दे पर केंद्रित थी।

न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी) के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अम्मान में 5-8 नवंबर, 2012 को आयोजित एशिया प्रशांत फोरम (ए पी एफ) के क्षेत्रीय समूह की बैठक, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था के 11वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, व्यावसायिक महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के लिए पार्श्व बैठक में भाग लिया। इसके अलावा, अम्मान के लिए किए अन्य सरकारी दौरों में तीसरा ग्लोबल फोकल प्वाइंट सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16-18 जुलाई, 2012 के दौरान श्री के. सलीम अली, विशेष निदेशक (एस), सीबीआई का दौरा; 17 से 21 मार्च, 2012 के दौरान डा0 एस. वाई. कुरैशी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा 05-06 अगस्त, 2012 के लिए रामाल्लाह (फिलीस्तीन) में आयोजित नाम मंत्रियों की समिति बैठक, जो आखिरी क्षण में रद्द हो गया था, में भाग लेने के लिए तत्कालीन सचिव (पूर्व) का 4 अगस्त, 2012 का दौरा शामिल है।

आवास तथा शहरी विकास विषय पर चौथे एशिया- प्रशांत मंत्री समूह सम्मेलन का आयोजन 10-12 दिसंबर, 2012 अम्मान में हुआ। तत्कालीन भारतीय राजदूत श्री आर. आर. डाश ने श्री सुशील कुमार, संयुक्त सचिव, शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन के साथ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

जॉर्डन के स्वतंत्र चुनाव आयोग के निमंत्रण पर भारतीय निर्वाचन आयोग के दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 23 जनवरी, 2013 को आयोजित संसदीय चुनाव हेतु जिला के अधिकारियों को प्रशिक्षण की तैयारी में मदद करने के लिए 02-10 जनवरी, 2013 के दौरान जॉर्डन का दौरा किया।

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री श्रीकांत के जेना ने 8-11 जुलाई, 2013 को जॉर्डन में सरकारी दौरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला एंसकौर, तत्कालीन व्यापार एवं उद्योग मंत्री, हातिम हालवानी तथा ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री, मालिक कबाराति से पृथक रूप से मुलाकात की। श्री आमेर मजालि, अध्यक्ष, जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी (जे पी एम सी) ने राज्य मंत्री तथा उनके साथ गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक की।

भारत और जॉर्डन के बीच विदेशी औपचारिक विचार-विमर्श अम्मान में 1 अप्रैल, 2014 को आयोजित हुए। श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व) भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जबकि जॉर्डन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व, मोहम्मद तैसीर बनी यासीन, जॉर्डन के हाशेमीते गणतंत्र के विदेश एवं प्रवासी मंत्रालय में महासचिव ने किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं विशेषकर राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा एवं संस्कृति के क्षेत्र के बारे में सकारात्मक विचार-विमर्श किया। श्री वाधवा ने श्री हातिम हालावानी, उद्योग, व्यापार एवं आपूर्ति मंत्री तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्री और श्री नासीर जुदेह, विदेश एवं प्रवासी मंत्री के साथ भी पृथक रूप से मुलाकात की। इस दौरे को स्थानीय समाचारपत्रों ने विस्तारपूर्वक एवं प्रमुखता से प्रकाशित किया। वह विदेश मंत्री के विशेष दूत के रूप में पुन: जुलाई 2014 में जार्डन की यात्रा पर गए तथा विदेश मंत्रालय में महासचिव श्री मोहम्मद तैसीर बानी यासेन से बातचीत की तथा विदेश मंत्री नासेर जुडेह से भी मुलाकात की।

सांसदों एवं विधायकों वाला एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 7-8 नवंबर, 2014 को मृत सागर में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संसदीय कार्रवाई में भाग लिया। इस समारोह का आयोजन जलवायु संसद तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया जिसमें संबंधित देशों की ऊर्जा संबंधी नीतियों पर विचार विमार्श किया गया। राजदूत त्रिगुणायत ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनके सम्मान में डिनर की मेजबानी की। प्रतिनिधिमंडलों ने जॉर्डन के अपने समकक्षों के साथ संसदीय सहयोग एवं आदान प्रदान को बढ़ावा देने में अपनी अभिरूचित व्यक्त की।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 30 मार्च 2015 को अम्मान में आयोजित संयुक्त आर्थिक समिति की 9वीं बैठक में भाग लेने के लिए 29 से 31 मार्च 2015 के दौरान जार्डन का दौरा किया। 29 से 31 मार्च 2015 तक अम्मान में अपने प्रवास के दौरान माननीय राज्य मंत्री ने उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री नसीर जुडेह और उद्योग, व्यापार एवं आपूर्ति मंत्री सुश्री माहा अली के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

भारत – जॉर्डन व्यापार 1976 में हस्ताक्षरित करार के तहत शासित होता है। इस करार के तहत गठित व्यापार एवं आर्थिक संयुक्त समिति व्यापार को बढ़ावा देता है और इस संबंध में प्रगति की निगरानी करता है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्षों के दौरान व्यापार संतुलन जॉर्डन के पक्ष में था जिसकी वजह भारत द्वारा फॉस्फेट एवं पोटाश का बड़े पैमाने पर आयात था। तथापि, वर्ष 2014-15 में द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2013-14 में 2.206 बिलियन अमेरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में 2.228 बिलियन अमेरीकी डालर हो गया और लगातार तीसरे वर्ष व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। इन दो देशों के बीच उर्वरक सेक्टर में सफल सहयोग रहा। फॉस्फोरिक एसिड के निर्माण हेतु इशिडिया में जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी (जे पी एम सी) तथा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (ईफको) के बीच 860 बिलियन अमेरीकी डॉलर की लागत से स्थापित संयुक्त उद्यम परियोजना का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी और महामहिम शाह अब्दुल्ला द्वारा किया गया। एम एम टी सी इंडिया लिमिटेड ने जून 2015 में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए जे पी एम सी के साथ एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया है। 300 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश से भारतीय उद्यमियों के स्वामित्व वाली दो दर्जन से अधिक टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का पश्चिम को एफ टी ए करारों के तहत जार्डन के निर्यात में पर्याप्त योगदान है। इराक, सऊदी अरब और चीन के बाद भारत जार्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है।

व्यापार से संबंधित सारणीबद्ध ब्योरा नीचे दिया गया है:-

बिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	कुल व्यापार टर्नओवर	भारत को निर्यात (बिलियन अमेरीकी डॉलर में)	भारत से आयात
2010-11	1.304	0.818	0.485
2011-12	2.304	1.483	0.821
2012-13	1.942	0.942	1.000
2013-14	2.206	0.610	1.595

2014-15	2.228	0.857	1.431

(स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

भारत जॉर्डन से उर्वरक, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड इत्यादि का आयात करता है और उसे वैद्युत मशीनरी, अनाज, जमा हुआ मांस, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, पशु आहार, इंजीनियरी एवं आटोमोटिव पुर्जों इत्यादि का निर्यात करता है।चमड़ा, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, नवीकरणीय उर्जा (सौर) तथा निर्माण क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की संभावनाएं भविष्य में तलाशी जा सकती हैं। नवगठित निवेश आयोग विशष रूप से आई सी टी, वित्त/ बैंकिंग सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) और जैव चिकित्सा सेवा क्षेत्रों में जार्डन में भारतीय निवेश सहित पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित कर रहा है।

30 मार्च 2015 को अम्मान में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमन और किंगडम आफ जार्डन की उद्योग, व्यापार एवं आपूर्ति मंत्री माननीया सुश्री माहा अली के नेतृत्व में भारत - जार्डन संयुक्त व्यापार एवं आर्थिक आयोग (जे टी ई सी) की 9वीं बैठक हुई। दोनों पक्षों ने जे टी ई सी की कार्यवाहियों पर संतोष व्यक्त किया जिसका आयोजन हमारे विशेष द्विपक्षीय संबंध और दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सकारात्मक रूझानों को देखते हुए इसके उन्नयन के बाद पहली बार मंत्री स्तर पर हुआ। दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की तथा उनकी समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार - विमर्श किया। इस बैठक के दौरान 2025 तक 5 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पर सहमति हुई। भारत - जार्डन व्यवसाय मंच की वार्षिक बैठक और संयुक्त व्यवसाय परिषद की बैठक जल्दी से आयोजित करने पर भी सहमति हुई। मंत्री स्तरीय बैठक से पूर्व 29 मार्च को वरिष्ठ अधिकार बैठक (एस ओ एम) हुई जिसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुद्दों के सभी पहलुओं पर विचार - विमर्श किया। यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय में श्रीमती सीतारमन ने जॉर्डन, इराक और भारत से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की श्रेष्ठ सभा को संबोधित किया। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रपति जी की राजकीय यात्रा के दौरान व्यापार एवं निवेश को बढ़ाने के लिए भारत ने जार्डन को 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है।

जॉर्डन में 10,000 से अधिक भारतीय नागरिकों का स्थायी निवास है जो वस्त्र, निर्माण एवं विनिर्माण सेक्टरों, उर्वरक कंपनियों, स्वास्थ्य सेक्टर, विश्वविद्यालयों, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय कंपनियों एवं बहुपक्षीय संगठनों मे कार्यरत हैं। पूरे जॉर्डन (अर्हता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र (क्यू आई जैड)) में पोशाक की लगभग 25 फैक्टरियां हैं। इन कंपनियों का स्वामित्व भारतीयों के पास है तथा इसमें 300 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है और 10,000 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।

उपयोगी संसाधन :

भारत का राजदूतावास, अम्मान वेबसाइट:
http://indembassy-amman.org/
भारत का राजदूतावास, अम्मान फेसबुक पृष्ठ:
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-India-Amman/
भारत का राजदूतावास, अम्मान ट्विटर पृष्ठ:
https://twitter.com/IndiainJordan

***

जनवरी, 2016